नईदुनिया

12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने की संभावना

अगले माह भारत आ सकते हैं पुतिन

मोदी से मुलाकात के संकेत, जयशंकर ने रूस पहुंचकर दिया न्योता

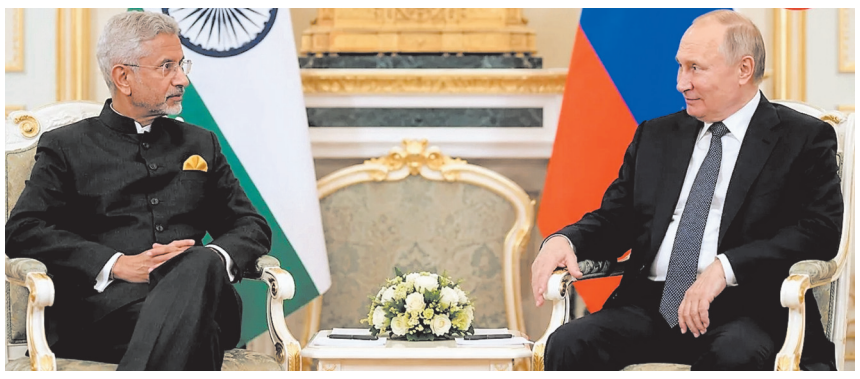

मॉस्को, एजेंसीः रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत आ सकते हैं। वह 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। मॉस्को में सोमवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं ने भारत-रूस संबंधों और आपसी सहयोग को लेकर चर्चा की।

जयशंकर रविवार को रूस के दो दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पुतिन का भारत में स्वागत करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के नेताओं की वार्षिक बैठक जल्द होगी। प्रधानमंत्री मोदी किर्गिजस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान भी पुतिन से मुलाकात की उम्मीद कर रहे हैं।

पुतिन ने जयशंकर से कहा कि उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच दशकों से कायम संबंधों की मजबूती को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश लगभग सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग जारी रखे हुए हैं। पुतिन के अनुसार, इस साल दोनों देशों के बीच कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन इस वर्ष कारोबार फिर बढ़ रहा है।

जयशंकर ने सोमवार को रूस के उपप्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत-रूस साझेदारी लगातार मजबूत हुई है और दोनों देशों के संबंध आपसी हित तथा भरोसे को दर्शाते हैं।

भारत और रूस के बीच व्यापार 2022 के बाद तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का कारोबार रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंचा था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर करीब 59.9 अरब डॉलर रह गया। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत और रूस के व्यापार में रूस से भारत को होने वाले कच्चे तेल के निर्यात की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत रूस से तेल के अलावा खाद, कोयला और अन्य कच्चा माल भी खरीदता है। वहीं, भारत रूस को दवाइयां, कृषि उत्पाद, मशीनरी और अन्य सामानों का निर्यात बढ़ाना चाहता है। जुलाई 2026 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 24.7 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल तेल आयात का 50.83 प्रतिशत था। जुलाई 2025 की तुलना में रूस से भारत का तेल आयात 62.4 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि जून 2026 के 26 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड की तुलना में जुलाई में आयात 4.8 प्रतिशत कम रहा।

उत्तराखंड के दुर्गम गांवों में अब ड्रोन पहुँचाएगा डाक

पौड़ी से शुरू होगा परीक्षण, असम और हिमाचल प्रदेश में तैयार किए जा चुके हैं करीब 150 ड्रोन मार्ग

नईदुनिया ब्यूरो, देहरादूनः उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी गांवों तक डाक और पार्सल पहुंचाने के लिए अब डाक विभाग ड्रोन का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रदेश में संभावित ड्रोन मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। योजना की शुरुआत पौड़ी जिले से किए जाने की संभावना है। पायलट परियोजना के तहत सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाएगा, जहां सड़क मार्ग से डाक पहुंचाने में अधिक समय लगता है। परीक्षण सफल रहने पर प्रदेश के अन्य पहाड़ी जिलों में भी ड्रोन के माध्यम से डाक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। इससे विशेष रूप से दूरस्थ गांवों तक डाक पहुंचने में लगने वाला समय कम होगा। उत्तराखंड में बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी के दौरान कई बार सड़क संपर्क बाधित हो जाता है। ऐसे में ड्रोन के माध्यम से डाक पहुंचाने की व्यवस्था सामान्य डाक और पार्सल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपदा के समय जरूरी दस्तावेज और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। डाक विभाग ने ड्रोन से डाक पहुंचाने का प्रारंभिक मॉडल असम और हिमाचल प्रदेश में तैयार किया है। दोनों राज्यों में करीब 150 ड्रोन मार्ग बनाए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ड्रोन के माध्यम से तिरंगा पहुंचाने का परीक्षण भी किया जा चुका है। इन प्रयोगों से मिले अनुभव के आधार पर अब उत्तराखंड के लिए ड्रोन डाक वितरण की योजना तैयार की जा रही है। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए हवाई मार्ग निर्धारित किए जाएंगे। शुरुआत उन इलाकों से किए जाने की योजना है, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना कठिन है और डाक पहुंचाने में अधिक समय लगता है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर व्यवस्था का विस्तार अन्य पहाड़ी क्षेत्रों तक किया जा सकेगा।

विद्यार्थी लोकतंत्र का भविष्यः ज्ञानेश कुमार

नईदुनिया ब्यूरो, लखनऊः मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि विद्यार्थी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं की समझ और लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनावी साक्षरता क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को लखनऊ में चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी 2.0) और ईसीआईनेट पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य युवा नागरिकों में चुनावी साक्षरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना था। इसमें उत्तर प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, कानून और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कराए जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों और युवा मतदाताओं को चुनाव प्रणाली, मतदाता पंजीकरण, मतदान और मतगणना प्रक्रिया की जानकारी देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में युवाओं का विश्वास और उनकी जागरूक भागीदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ईएलसी 2.0 का उद्देश्य युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को लोकतंत्र को समझने और उसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पुराने विद्यालय कोल्विन तालुकदार कॉलेज का दौरा कर शिक्षकों और छात्रों से बातचीत भी की। मंगलवार को वह उत्तर प्रदेश के बूथ स्तरीय अधिकारियों से संवाद करेंगे। ईएलसी 2.0 के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चुनावी साक्षरता क्लबों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को चुनाव से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ईसीआईनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नामांकन से लेकर मतदान तक की सेवाएं उपलब्ध होंगी।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव 2029 में हो सकते हैं एक साथ, फैसला राज्य तय करेगा

संसदीय समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया- राज्यों की सहमति और संसद की मंजूरी होगी अहम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वर्ष 2029 में एक साथ कराए जा सकते हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन पर गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने सोमवार को कहा कि इसके लिए संविधान में संशोधन और राज्यों की सहमति आवश्यक होगी।

पीपी चौधरी ने कहा कि यदि संसद वर्ष 2028 तक संविधान संशोधन को मंजूरी दे देती है तो एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था उसी वर्ष शुरू की जा सकती है। हालांकि, 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला राज्यों की इच्छा और सहमति पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की इस मुद्दे पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन समिति देशहित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी उनकी राय जानने के लिए समिति के सामने बुलाया गया है।

संसद ने वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़े संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर सिफारिशें देने की जिम्मेदारी 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति को सौंपी है। इन विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। राजस्थान से भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने इससे पहले महाराष्ट्र और उत्तराखंड का दौरा कर विभिन्न पक्षों से चर्चा की थी। महाराष्ट्र में समिति ने मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थाओं से बातचीत कर एक साथ चुनाव कराने के प्रभावों पर जानकारी ली थी। उत्तराखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य अधिकारियों ने समिति को बताया था कि बार-बार चुनाव होने से आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने एक साथ चुनाव होने पर खर्च में कमी आने की संभावना भी जताई थी।

वन नेशन, वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों से चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी।

लोकतंत्र की ताकत से आम व्यक्ति भी सीएम-पीएम बन सकता हैः देवेन्द्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोले- संविधान अवसर देता है, लगन और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता

नईदुनिया ब्यूरो, नागपुरः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की ताकत ऐसी है कि सामान्य पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में अभिनेता एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है। लोकतंत्र व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देता है।

फडणवीस ने कहा कि जो व्यक्ति कभी पार्षद बनने की कल्पना भी नहीं करता था, वह मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी तरह गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी लगन से अपना लक्ष्य तय कर ले तो लोकतंत्र और संविधान उसे आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन को याद करते हुए कहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। उस समय उनकी पार्टी विपक्ष में थी और उन्हें लगता था कि शायद वह हमेशा विपक्ष की राजनीति ही करेंगे। हालांकि, जनता के भरोसे के कारण वह धीरे-धीरे आगे बढ़े और मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी मिली।

मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष की उम्र में वह प्रयागराज से अयोध्या की ओर गए थे। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

उनके अनुसार, उन्होंने बदायूं केंद्रीय जेल में 18 दिन बिताए। जेल से लौटने के बाद वह फिर आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के समय भी वह वहां मौजूद थे और उन्हें इस पर गर्व है।

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नीति तैयार की है। इसके तहत कोष बनाए गए हैं और उद्भवन केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे शहर का कोई युवा विचार लेकर आता है और उसे व्यावसायिक उत्पाद में बदलना चाहता है तो सरकार उसे पूरी मदद और समर्थन देगी।

अमेरिका में एच-1बी वीजा पर 98 लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क लेने का प्रस्ताव

ट्रंप प्रशासन ने जारी किया नया प्रस्ताव, साल के अंत तक लागू हो सकता है नियम; भारतीय आईटी पेशेवरों पर सबसे ज्यादा असर की संभावना

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को ॥-1क्कवीजा के लिए नया प्रस्ताव जारी किया है। इसके तहत विदेशी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक एच-1बी वीजा पर 1,03,265 डॉलर यानी करीब 98 लाख रुपये की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव है। नया नियम लागू होने पर एच-1बी वीजा पहले की तुलना में काफी महंगा हो जाएगा।

एच-1बी गैर-आप्रवासी वीजा है, जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशों से उच्च कौशल वाले पेशेवरों को सीमित अवधि के लिए नौकरी पर रखती हैं। पहले इस वीजा के लिए सामान्य तौर पर करीब 2,000 से 5,000 डॉलर तक शुल्क लगता था। प्रस्तावित नई फीस इससे कई गुना अधिक है। नया नियम साल के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। इस प्रस्ताव का सबसे ज्यादा असर भारतीय आईटी और तकनीकी पेशेवरों पर पड़ सकता है। बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारी एच-1बी वीजा के जरिए अमेरिका में काम करते हैं। तकनीकी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण छंटनी और नए आव्रजन नियमों के चलते विदेशी कर्मचारियों की भर्ती पहले ही प्रभावित हुई है।

पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने अस्थायी आदेश के जरिए एच-1बी वीजा पर अतिरिक्त फीस लागू की थी। हालांकि, जून में अमेरिकी संघीय अदालत ने इसे गैरकानूनी बताते हुए सरकार को फीस वसूलने से रोक दिया था। फिलहाल बोस्टन की एक अपीलीय अदालत इस फैसले की समीक्षा कर रही है। वहीं, वॉशिंगटन डीसी की दूसरी अदालत में भी इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई चल रही है। नए प्रस्ताव में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग को अतिरिक्त शुल्क को स्थायी बनाने के लिए नियम तैयार करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने प्रस्ताव को संघीय रजिस्टर की वेबसाइट पर जारी किया है। इसके औपचारिक प्रकाशन के बाद आम लोगों, कंपनियों और संगठनों को 30 दिनों तक अपनी राय देने का अवसर मिलेगा। पिछले साल कंपनियों ने करीब 3.44 लाख एच-1बी वीजा के लिए पंजीकरण कराया था, जो 2024 की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक कम था। नौकरी गंवाने वाले एच-1बी कर्मचारियों को नया रोजगार तलाशने के लिए 60 दिनों का समय मिलता है। नए शुल्क और सख्त आव्रजन नियमों से भारतीय कर्मचारियों पर दबाव और बढ़ सकता है।

जब गुजरात के मुख्यमंत्री को अनुमति मिली, मेरी यात्रा रोकना राज्य का अपमान : रेड्डी

नईदुनिया ब्यूरो, हैदराबादः तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा को मंजूरी नहीं देना तेलंगाना का अपमान है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि केंद्र ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अमेरिका यात्रा को अनुमति दी, जबकि उनकी यात्रा को राजनीतिक आधार पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल का अमेरिका दौरा प्रस्तावित था। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर यात्रा के लिए मंजूरी देने से इनकार किया। हालांकि, केंद्र ने उनके ब्रिटेन दौरे को अनुमति दी थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने उनके प्रस्ताव की समीक्षा के बाद राजनीतिक दृष्टिकोण से मंजूरी नहीं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि यदि उनकी विदेश यात्रा में कोई राजनीतिक गतिविधि शामिल नहीं थी तो पहले यात्रा की अनुमति क्यों दी गई। रेवंत रेड्डी 20 अगस्त को लंदन पहुंचे थे।

योजना

रूस की सीमा के भीतर तक हमला करने में सक्षम मिसाइल के उत्पादन की तैयारी, मॉस्को ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी...

कीव में बनेगी लंबी दूरी की स्काल्प मिसाइल, ब्रिटेन देगा तकनीक

कीव, एजेंसीः रूस के खिलाफ जारी युद्ध में यूक्रेन की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रिटेन उसे अपनी गुप्त मिसाइल तकनीक देगा। इससे यूक्रेन में ही लंबी दूरी की स्काल्प क्रूज मिसाइल के उत्पादन का रास्ता साफ होगा। ब्रिटेन में इसी मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम सोमवार को अपनी पहली विदेश यात्रा पर यूक्रेन पहुंचे। इस दौरान मिसाइल तकनीक साझा करने की घोषणा की गई। वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। फ्रांस और यूक्रेन की योजना इस साल के अंत तक यूक्रेन में स्काल्प के उत्पादन की लाइन शुरू करने की है।

स्काल्प यूरोपीय हथियार कंपनी एमबीडीए द्वारा निर्मित विमान से दागी जाने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 550 किलोमीटर है और इसमें लगभग 400 किलोग्राम का भारी विस्फोटक लगाया जा सकता है। मिसाइल का वजन करीब 1,300 किलोग्राम और लंबाई लगभग 5.10 मीटर है।

यह मिसाइल पहले से निर्धारित ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई है। विमान से छोड़े जाने के बाद यह जमीन के काफी

करीब उड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचती है। इसमें उपग्रह आधारित मार्गदर्शन, इलाके की पहचान और गर्मी के आधार पर लक्ष्य पहचानने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह दुश्मन की हवाई सुरक्षा व्यवस्था से बचते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करती है।

ब्रिटेन के फैसले पर रूस ने कड़ी नाराजगी जताई है। ब्रिटेन स्थित रूसी दूतावास ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन जानबूझकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। दूतावास ने चेतावनी दी कि युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी जितनी बढ़ेगी, उसे इसकी कीमत उतनी ही अधिक चुकानी पड़ेगी। वहीं, एंडी बर्नहम ने कहा कि ब्रिटेन लंबे समय तक यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा और यूक्रेन की सुरक्षा ब्रिटेन की सुरक्षा से जुड़ी है।

यूक्रेन ने भी लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता बढ़ाई है। यूक्रेनी कंपनी फायर प्वाइंट ने करीब 3,000 किलोमीटर तक मार करने वाली एफपी-5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल विकसित की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार, इसका इस्तेमाल रूस के भीतर करीब 900 किलोमीटर दूर एक रॉकेट इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने पर हमले के लिए किया गया था।

यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई यूरोपीय नेता भी कीव पहुंचे। इनमें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन, मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संदू और एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस शामिल हैं। इस बीच यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के लिए करीब 68 हजार करोड़ रुपये की नई सैन्य सहायता मंजूर की है। यह राशि हवाई सुरक्षा प्रणाली, मिसाइल, गोला-बारूद और रडार खरीदने पर खर्च की जाएगी।